

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण रविवार 25 जनवरी 2026 वर्ष-9, अंक-03 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रुपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com  www.facebook.com/krantisamay1  www.twitter.com/krantisamay1

बहुत जल्द भारत बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन

कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का कभी नहीं किया विरोध

इसरो ने शुरू किया काम, एक और छलांग की है तैयारी



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और छलांग लगाने की तैयार कर रहा है। स्पेस एजेंसी ने अपनी अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव रख दी है। भारतीय उद्योग जगत को साथ आने का न्योता दिया है। यह कदम भारत को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास अंतरिक्ष में अपना स्थायी ठिकाना (स्टेशन) है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने भारतीय कंपनियों के लिए एक्सप्रेसन ऑफ

इंटरैस्ट जारी किया है। इसके जरिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल, ईआर-01 के निर्माण के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहले चरण की शुरुआत 2028 में होगी। इसमें अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल (ईआर-01) को लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है।

2035 तक इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी 5 मॉड्यूल के साथ स्टेशन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 400-450 किमी की ऊंचाई पर स्थापित होगा। शुरुआत में यह 3-4 अंतरिक्ष यात्रियों को ठहराने और वहां वैज्ञानिक प्रयोग करने में



सक्षम होगा। इसरो ने भारतीय कंपनियों के लिए कड़े मानक तय किए हैं, क्योंकि यह मॉड्यूल इसानों के रहने योग्य होगा। प्रत्येक मॉड्यूल 3.8 मीटर व्यास और 8 मीटर ऊंचा होगा। इसका निर्माण उच्च शक्ति वाले एल्युमिनियम

मिश्र धातु (ए-2219) से किया जाएगा। निर्माण में 0.5 मिलीमीटर की भी गलती स्वीकार्य नहीं होगी। कंपनियों को विशेष वेलिंग और फैब्रिकेशन तकनीक विकसित करनी होगी। इसरो ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी तरह भारतीय प्रयास होगा। इसमें किसी भी विदेशी सहायता या आउटसोर्सिंग की अनुमति नहीं होगी। जो कंपनियां इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती हैं उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। कम से कम 5 साल का एरोस्पेस निर्माण का अनुभव हो। पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 50 करोड़ हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च 2026 तक की गई है। यह परियोजना केवल एक स्टेशन बनाने तक सीमित नहीं है।

● थरूर बोले-केवल ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर असहमति थी

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि मैंने पार्लियामेंट में कांग्रेस के किसी भी स्टैंड का किसी भी स्टैंड पर विरोध नहीं किया है। एकमात्र मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर था, जिस पर सिद्धांत के आधार पर पब्लिक में असहमति हुई।

उन्होंने कहा- इस मामले पर मैंने बहुत मजबूत स्टैंड लिया था। मैं उसके लिए कोई माफी नहीं मांगूंगा। पहलगाम की घटना के बाद, मैंने खुद एक कॉलम लिखा था। मैंने इसमें कहा था कि ऐसी घटना को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता और इसका जवाब देना जरूरी है। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने ये बातें शनिवार को

कोशिकोड में आयोजित केरल लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कहीं। वह वहां दर्शकों के सवाल का जवाब दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर कड़े रुख का कोई पछतावा नहीं है। भारत को विकास पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान के साथ लंबे संघर्ष में नहीं उलझना चाहिए। किसी भी कार्रवाई को आतंकवादी शिविरों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। मुझे हैरानी हुई कि भारत सरकार ने वही किया, जैसा मैंने सुझाया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था अगर भारत मर जाता है, तो कौन जीवित रहेगा। उनका कहना था कि जब देश की सुरक्षा और दुनिया में उनकी स्थिति का सवाल हो, तो भारत सबसे पहले आता है।



पीएम ने 61 हजार से अधिक युवाओं को दी सौगात

रोजगार मेले में मोदी ने युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को रोजगार मेले में सरकारी नौकरियों के 61,000 नियुक्ति पत्र सौंपे। 18वें रोजगार मेले के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में ये नियुक्तियां की जाएंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, आज के इस महत्वपूर्ण

तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी का दौर

पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तेजी से बदल रही हैं। इस तेज बदलाव के साथ आपको खुद को अपग्रेड करते रहना है। उन्होंने



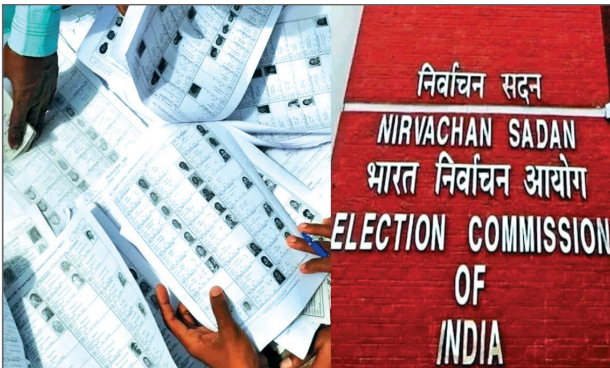
दिन देश के 61 हजार से अधिक नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सभी को सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। यह विकसित भारत के निर्माण की गति देने का संकल्प पत्र है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कहा, साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब बसंत पंचमी कल ही गई है तो आपके जीवन में भी ये नई बसंत का आरंभ हो रहा है। आपको ये समय संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है।

कहा, मुझे खुशी है कि इतने कम समय में करीब डेढ़ करोड़ सरकारी कर्मचारी इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर खुद को नए सिर से ट्रेड कर रहे हैं, इम्प्रावर कर रहे हैं। हम सभी के लिए एक मंत्र है- नागरिक देवो भवः। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य, देश में जीवन और कारोबार, दोनों को आसान बनाने का है। उन्होंने कहा, आज के इस आयोजन में 8 हजार से ज्यादा बेटीयों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश के वर्कफोर्स में, वीमेन पार्टिसिपेशन में करीब कहीं दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि आज भारत सरकार, अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये भारत के युवाओं के लिए अवसर है।

चुनाव आयोग के दिल्ली डिवलेशन पर बनी सहमति

नई दिल्ली (एजेंसी)। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने अपने यहां मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए इसी तरह का तरीका अपनाने पर बल दिया है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 'लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन' पर आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने आए 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों और 27 देशों के मिशन प्रमुख ने सर्वसम्मति से अपने यहां भी मतदाता सूची के शुद्धीकरण के लिए अपनी-अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

'लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन' (आईआईसी डीईएम-2026) के अंतिम दिन विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों ने 'शुद्ध' मतदाता सूची बनाने और हर मतदाता को



फोटो पहचान पत्र देने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। सम्मेलन के समापन सत्र में 'दिल्ली के घोषणा 2026' को पढ़ते हुए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इसमें शामिल सभी चुनाव प्रबंधन निकायों ने घोषणा पत्र के पांच स्तंभों पर एक साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया है जो 'मतदाता सूची की शुद्धता, चुनाव संचालन,

अनुसंधान और प्रकाशन, प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सभी ने अपनी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने का भी संकल्प लिया और 3, 4 और 5 दिसंबर 2026 को भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में दोबारा से मिलने का प्रस्ताव दिया, जिसे सभी ने स्वीकार किया।

शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव

समापन सत्र में ज्ञानेश कुमार ने कहा, कानून के अनुसार सभी मतदाताओं के नाम वाली शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव है। निकायों को चुनावों के आसान और पारदर्शी संचालन के लिए सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। सम्मेलन में 42 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुखों/प्रतिनिधियों और 27 देशों के मिशन प्रमुखों सहित लगभग 1,000 लोगों ने भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के नेतृत्व में प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों व अन्य ने गहन विचार-विमर्श में योगदान दिया।

ठाकरे भाई अब नहीं होंगे अलग! हो गया फैसला

● बालसाहेब के जन्मदिन पर छलका प्यार, खूब बर्जी तालियां



मुंबई (एजेंसी)। साल 2025 में जब हिंदी-मराठी भाषा विवाद को लेकर उद्भव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए थे तो राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा था कि दोनों भाइयों में मेल-मिलाप नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके बाद दोनों भाइयों ने मुंबई बीएमसी समेत महाराष्ट्र में महानगरपालिका के चुनाव साथ-साथ लड़े। बीएमसी में राज ठाकरे की अगुवाई वाली मनसे को सिर्फ 6 सीटें मिलने के बाद विश्लेषण में कहा जा रहा है कि राज-उद्भव ठाकरे कितने दिन साथ रहेंगे। इन तमाम कयासबाजी के बीच शुक्रवार को ठाकरे भाइयों की गजब की केमिस्ट्री सामने आई। जब शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के 100वें जन्मदिन (जन्म शताब्दी) के मौके पर दोनों भाई एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। दोनों ने एक साथ रहने का फैसला लिया है।

शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव का किया शंखनाद

लखनऊ में बोले-सपा-बसपा परिवारवादी, ये आपका कल्याण नहीं करेंगी



लखनऊ (एजेंसी)। गुहमंजी अमित शाह ने लखनऊ में यूपी विधानसभा चुनाव- 2027 का शंखनाद कर दिया। शाह ने लोगों से कहा- सपा, बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं। ये आपका कल्याण नहीं सकतीं। 2027 में ऐसी पार्टियों को रिजेक्ट कर एक बार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। यूपी का कल्याण सिर्फ भाजपा ही कर सकती है।

शाह यूपी दिवस समारोह के लिए लखनऊ आए थे। उन्होंने 24-26 जनवरी तक चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। हर जिले के पारंपरिक व्यंजनों को दुनियाभर में पहचान दिलाने के लिए एक जनपद, एक व्यंजन योजना की शुरुआत भी की। उन्होंने जय श्रीराम का जयकारा लगाकर अपने संबोधन की शुरुआत की। भारत माता की जय के भी नारे लगाए। लोगों से

कहा- आज यूपी दिवस है भाई, लखनऊ वालों की आवाज को क्या हो गया। इसके बाद लोगों ने जोर से शाह के साथ नारे लगाए। इससे पहले, सीएम योगी ने पीएम मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने 2017 में यूपी में भाजपा की जीत का श्रेय शाह को दिया। साथ ही जनता से अपील की कि 2027 में फिर से भाजपा सरकार बनाएं। कार्यक्रम में एग्सेक्यूटिव शुभांशु शुक्ला समेत 5 लोगों को यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। शाह ने अलग-अलग जिलों के फेमस व्यंजनों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया। शाह और योगी साथ चलते दिखाई दिए। पीछे दोनों डिप्टी सीएम और बीच में पंकज चौधरी चल रहे थे।

बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान अब नहीं गाएंगी 'बीड़ी जलाई ले'

● चंडीगढ़ के प्रोफेसर की शिकायत पर चाइल्ड राइट्स कमीशन का नोटिस, कहा- बुरा असर पड़ेगा

चंडीगढ़ (एजेंसी)। फेमस बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान को चंडीगढ़ के प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धरेन्नावर की शिकायत पर नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस दक्षिण गोवा जिला बाल संरक्षण इकाई ने जारी किया है। इसमें सिंगर को बीड़ी जलाई ले और शराबी या ऐसे ही सांग गाने ना देने के कहा गया है। बता दें कि सिंगर का कल या यानी 25 जनवरी को गोवा के 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम में 'द अल्टीमेट सुनिधि लाइव कॉन्सर्ट' है। इसे लेकर प्रोफेसर डॉ. धरेन्नावर ने शिकायत की थी, जिसमें आयोजकों को बच्चों की मौजूदगी में तंबाकू और शराब को बढ़ावा देने वाले गाने न बजाने और न गाने देने की प्रिवेंटिव एडवाइजरी करने की मांग की थी। इसी शिकायत के बाद गोवा चाइल्ड कमीशन ने सिंगर सुनिधि चौहान के लाइव कॉन्सर्ट को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

तिरुवनंतपुरम नगर-निगम ने बीजेपी पर लगाया जुर्माना

● यहां बीजेपी का ही मेयर, पीएम के दौरे पर पलैक्स बोर्ड लगाने को लेकर पुलिस केस भी दर्ज



मोदी के केरल दौरे के दौरान शहर में फुटपाथों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाने पर लगाया गया है। बोर्ड लगाने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। न्यूज

एजेंसी के मुताबिक तिरुवनंतपुरम नगर निगम के सचिव की शिकायत के बाद कैटोनमेंट पुलिस ने शुक्रवार देर रात बीजेपी जिला अध्यक्ष कर्मना जयन के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिसंबर में हुए नगर निगम चुनाव में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने 50 सीटें जीती थीं। इसके बाद 26 दिसंबर को बीजेपी के वीवी राजेश को यहां का मेयर बनाया गया था। एफआईआर में केरल हाई कोर्ट के कई आदेशों और स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन का आरोप है। इसमें कहा गया कि बीजेपी जिला समिति ने प्रधानमंत्री के दौरे के हिस्से के रूप में फुटपाथों पर फ्लेक्स बोर्ड लगाए। इससे पालियम जंक्शन से पुलिमुड्ड जंक्शन तक जनता को असुविधा हुई।

प्रजातंत्र को वास्तविक गणतंत्र में बदलने की जरूरत



प्रो.संजय द्विवेदी

भारी संख्या में युवा शक्तियों से सुसज्जित देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अब किसी भी सीमा को तोड़ने को आतुर है। युवाशक्ति तेजी के साथ नए-नए विषयों पर काम कर रही है, जिसने हर क्षेत्र में एक ऐसी प्रयोगधर्मी और प्रगतिशील पीढ़ी खड़ी की है, जिस पर दुनिया विस्मित है।

आजादी के लगभग 8 दशक पूरे करने के बाद भारतीय गणतंत्र एक ऐसे मुकाम पर है, जहाँ से उसे सिर्फ आगे ही जाना है। अपनी एकता, अखंडता और सांस्कृतिक व नैतिक मूल्यों के साथ पूरी हुई इन 8 दशकों की यात्रा ने पूरी दुनिया के मन में भारत के लिए एक आदर पैदा किया है। यही कारण है कि हमारे भारतवंशी आज दुनिया के हर देश में एक नई निगाह से देखे जा रहे हैं। उनकी प्रतिभा का आदर और मूल्य भी उन्हें मिल रहा है। हमें सोचना होगा कि आखिर हम उस सपने को कैसा पूरा कर सकते हैं जिसे पूरे करने के लिए सिर्फ कुछ साल बचे हैं। यानि 2047 में भारत को महाशक्ति और विश्वगुरु बनाने का सपना।

आजादी के लड़ाई के मूल्य आज भले थोड़ा धुंधले दिखते हों या राष्ट्रीय पर्व औपचारिकताओं में लिपटे हुए, लेकिन यह सच है कि देश की युवाशक्ति आज भी अपने राष्ट्र को उसी जज्बे से प्यार करती है, जो सपना हमारे सेनानियों ने देखा था। आजादी की जंग में जिन नौजवानों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, वही ललक और प्रेरणा आज भी भारत के उत्थान के लिए नई पीढ़ी में दिखती है। हमारे प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र में भले ही संवेदना घट चली हो, लेकिन आम आदमी आज भी बेहद ईमानदार और नैतिक है। वह सीधे रास्ते चलकर प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहता है। यदि ऐसा न होता तो विदेशों में जाकर भारत के युवा सफलताओं के इतिहास न लिख रहे होते। जो विदेशों में गए हैं, उनके सामने यदि अपने देश में ही विकास के समान अवसर उपलब्ध होते तो वे शायद अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए प्रेरित न होते। बावजूद इसके विदेशों में जाकर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और ईमानदारी से भारत के लिए एक ब्रांड एक्सेसटर का काम किया है। यही कारण है कि सॉफ़, स्पेरों और साधुओं के रूप में पहचाने जाने वाले भारत की छवि आज एक ऐसे तेजी से प्रगति करने राष्ट्र के रूप में बनी है, जो तेजी से अपने को एक महाशक्ति में बदल रहा है। आर्थिक सुधारों की तीव्र गति ने भारत को दुनिया के सामने एक ऐसे चमकीले क्षेत्र के रूप में स्थापित कर दिया है, जहाँ व्यवसायिक विकास की भारी संभावनाएँ देखी जा रही हैं। यह अकारण नहीं है कि तेजी के साथ भारत की तरफ विदेशी राष्ट्र आकर्षित हुए हैं। बाजारवाद के हो-हल्ले के बावजूद आम भारतीय की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों में व्यापक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। ये परिवर्तन आज भले ही मध्यवर्ग तक सीमित दिखते हों, इनका लाभ आने वाले समय में नीचे तक पहुँचेंगा।

आकांक्षायान भारत का उदय:
भारी संख्या में युवा शक्तियों से सुसज्जित देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अब किसी भी सीमा को तोड़ने



को आतुर है। युवाशक्ति तेजी के साथ नए-नए विषयों पर काम कर रही है, जिसने हर क्षेत्र में एक ऐसी प्रयोगधर्मी और प्रगतिशील पीढ़ी खड़ी की है, जिस पर दुनिया विस्मित है। सूचना प्रौद्योगिकी, फिल्में, कृषि और अनुसंधान से जुड़े क्षेत्रों या विविध प्रदर्शन कलाएँ हर जगह भारतीय प्रतिभाएँ वैश्विक संदर्भ में अपनी जगह बना रही हैं। शायद यही कारण है कि भारत की तरफ देखने का दुनिया का नजरिया पिछले एक दशक में बहुत बदला है। ये चीजें अनायास और अचानक घट गई हैं, ऐसा भी नहीं है। देश के नेतृत्व के साथ-साथ आम आदमी के अंदर पैदा हुए आत्मविश्वास ने विकास की गति बहुत बढ़ा दी है। भ्रष्टाचार और संवेदनहीनता की तमाम कहानियों के बीच भी विश्वास के बीज धीरे-धीरे एक वृक्ष का रूप ले रहे हैं। कई स्तरों पर बंटे समाज में भाषा, जाति, धर्म और प्रांतवाद की तमाम दीवारें हैं। कई दीवारें ऐसी भी कि जिन्हें हमने खुद खड़ा किया है और हमारा बुरा सोचने वाली ताकतें उन्हें सबल दे रही हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर भी जब देश बँटा हुआ नजर आता है, तो कई बार आम भारतीय का दुख बढ़ जाता है। घुसपैठ की समस्या भी एक ऐसी समस्या है जिससे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। किसी तरह भी वोट बैंक बनाने और सत्ता हासिल करने की होड़ ने तमाम मूल्यों को शीर्षासन करा दिया है। ऐसे में जनता के विश्वास की रक्षा कैसे की जा सकती है? आजादी के इतने साल के बाद लगभग वही सवाल आज भी खड़े हैं, जिनके चलते देश का

बैटवारा हुआ और महात्मा गांधी जैसी विभूतियाँ भी इस बैटवारे को रोक नहीं पाईं। देश के अनेक हिस्सों में चल रहे अतिवादी आंदोलन, चाहे वे किसी नाम से भी चलाए जा रहे हों या किसी भी विचारधारा से प्रेरित हों। सबका उद्देश्य भारत की प्रगति के मार्ग में रोड़े अटकाना ही है। अनेक विकास परियोजनाओं के खिलाफ झंका हरतक्षेप यह बताता है कि सारा कुछ बेहतर नहीं है। गणतंत्र को सार्थक करने के लिए हमें साधन संपन्नों और हाशिये पर खड़े लोगों को एक तल पर देखना होगा। क्योंकि आजादी तभी सार्थक है, जब वह हिंदुस्तान के हर आदमी को समान विकास के अवसर उपलब्ध कराए। कानून की नजर में हर आदमी समान है, यह बात नारे में नहीं, व्यवहार में भी दिखनी चाहिए।

अंतिम आदमी का कीजिए विचार-
गणतंत्र के बारे में कहा जाता है कि वह सो सारलों में साकार होता है। भारत ने इस यात्रा की भी काफ़ी यात्रा पूरी कर ली है। बावजूद इसके हमें डा. राममनोहर लोहिया की यह बात ध्यान रखनी होगी कि हलोकराज लोकलराज से चलता है। इसी के साथ याद आते हैं पं. दिनदयाल उपाध्याय जैसे लोग, जिन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन देकर भारतीय राजनीति को एक ऐसी दृष्टि दी है, जिसमें आम आदमी के लिए जगह है। यह दर्शन हमें दरिद्रनाशयण की सेवा की मार्ग पर प्रशस्त करता है। महात्मा गांधी भी अंतिम व्यक्ति का विचार करते हुए उसके लिए इस तंत्र में जगह बनाने की बात करते हैं। हमें सोचना होगा कि गणतंत्र के इन वर्षों में उस आखिरी

आदमी के लिए हम कितनी जगह और कितनी संवेदना बना पाए हैं। प्रगति और विकास के सूचकांक तभी सार्थक हैं, जब वे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लाने में समर्थ हों। क्या ऐसा कुछ बताने और कहने के लिए हमारे पास है? यदि नहीं...तो अभी भी समय है भारत को महाशक्ति बनाना है, तो वह हर भारतीय की भागीदारी से ही सच होने वाला सपना है। देश के तमाम वंचित लोगों को छोड़कर हम अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। क्या हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं।

तलाशिएं सवालों के जवाब:
गणतंत्र दिवस इन तमाम सवालों के जवाब खोजने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है। बीते समय में आतंकवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रीयता की तमाम गंभीर चुनौतियों के सामने हमारा तंत्र बहुत बेबस दिखा। बावजूद इसके लोकतंत्र में जनता की आस्था बची और बनी हुयी है। हमारी एकता को तोड़ने और मन को तोड़ने के तमाम प्रयासों के बावजूद आम हिंदुस्तानी अपनी समूची निष्ठा से इस देश को एक देखना चाहता है। यह संकल्प लेना होगा कि हम लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को जगा पाएं। उनकी उम्मीदों पर अवसाद की परतें न चढ़ने दें। सपनों में रंग भरने की हिम्मत, ताकत और जोश से भरा हो- आम हिंदुस्तानी तो इसी सपने को सच होते हुए देखना चाहता है। यह संयोग ही है कि नया साल और गणतंत्र दिवस हम एक ही महोत्सव जनवरी में मनाते हैं। जाहिर तौर पर हर नए साल का मतलब कलैंडर का बदलना भर नहीं है वह उत्सव है संकल्प का, अपने गणतंत्र में तेज भरने का। आम आदमी में जो भरोसा टूटना दिखता है उसे जोड़ने का। गणतंत्र को तोड़ने या कमजोर करने में लगी ताकतों के मंसूबों पर पानी फेरने का। जनवरी का महिना इसीलिए बहुत खास है क्योंकि यह महिना देश की अस्मिता को पहली बार झकझोर कर जगाने वाले सन्यासी विवेकानंद की जन्मतिथि(12 जनवरी) का महिना है। जिन्होंने पहली बार भारत के दर्शन को विश्वमंच पर मान्यता दी नहीं दिलायी हमारे दबे-कुचले आत्मविश्वास को जागृत किया। यह महिना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन (23 जनवरी) का जिन्होंने विश्वी सत्ता के दांत चकाने पर दिए और विदेशी भूमि पर भारतीयों के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी सेना खड़ी की। जाहिर तौर पर यह महिना सही संकल्पों और महानायकों की याद का महिना है। इससे हमें प्रेरणा लेने और आगे बढ़ने की जरूरत है। नए साल का सूरज हमें एक नयी रोशनी दे रहा है उसका उजास हमें नई दृष्टि दे रहा है। क्या हम इस रोशनी से सबक लेकर, अपने महानायकों की याद को बचाने और देश को महाशक्ति बनाने के सपने के साथ खड़ा होने का हौसला दिखाएंगे?

संपादकीय

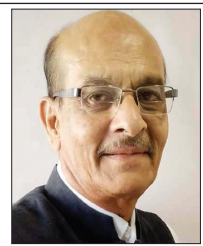
प्रदूषण बनाम टैरिफ

दावोस में हाल ही में संपन्न वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा के दौरान यह बात शिद्दत से उठी कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण ज्यादा घातक असर दिखा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और आईएमएफ की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने इकोनॉमिक फोरम में चर्चा के दौरान कहा कि व्यापार बढ़ाने की कवायद में अकसर व्यापारिक बाधाओं और नियमों की बात की जाती है, लेकिन आर्थिक तरक्की में बाधक प्रदूषण जैसे घटकों की चर्चा कम ही होती है। चर्चा में भारत में प्रदूषण की भयावहता का जिक्र करते हुए कहा गया कि भारत पर ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुकाबले प्रदूषण का असर ज्यादा घातक व दूरगामी है। फोरम में साल 2022 में विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया गया कि भारत में हर साल सत्रह लाख लोगों की मौत प्रदूषण से हो जाती है। ये आंकड़ा भारत में मरने वालों का अन्नूरह फोसदी बैठता है। जो कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों को बाधित करने के साथ ही बहुमूल्य जीवन भी लीलाता है। कमीबेश यह घातकता जीडीपी पर भी असर डालती है। निस्संदेह, प्रदूषण से होने वाली मौतों से केवल एक परिवार ही नहीं, पूरे देश पर प्रभाव पड़ता है। देश की श्रम शक्ति का ह्रास होता है और आर्थिकी पर दूरगामी प्रभाव होते हैं। वहीं आर्थिकी पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि प्रदूषण के चलते निवेशकों के भरोसे पर भी दुष्प्रभाव होता है। इससे निवेशकों का आकर्षण कम होता है। निस्संदेह, निवेशक के मन में भय होता है कि यदि वह इसी प्रदूषित वातावरण में रहता है तो वह उसके लिये यह घातक हो सकता है। इसमें दो राय नहीं कि प्रदूषण की भयावह स्थिति दुनिया में किसी भी देश की छवि को नुकसान जरूर पहुंचाती है। जिससे निवेशक बेहतर विकल्प की तलाश में अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। ऐसे में प्रदूषण के संकट को युद्धस्तर पर निपटाने की जरूरत महसूस की जा रही है। निस्संदेह, भारत में प्रदूषण का संकट एक यथार्थ है। यह भी हकीकत है कि देश के नीति-निर्यंता प्रदूषण संकट के समाधान को लेकर गंभीर नजर नहीं आते। जब-जब प्रदूषण संकट गहराता है तो आग लाने पर कुआँ खोदने की कवायद की जाती है। कोर्ट की फटकार व न्यायाक एजेंसियों की सख्ती के बाद शासन-प्रशासन हरकत में आता है। लेकिन गीता गोपीनाथ के तर्कों के कुछ अर्धसत्य भी हैं। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका के इशारे पर काम करने वाली वैश्विक एजेंसियाँ विकासशील देशों की लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से प्रतीक-प्रतिमान गढ़ती रही हैं। आईएमएफ जैसी संस्थाओं को अमेरिकी कूटनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहां तक कि इन संस्थाओं में उच्च पदों पर बैठे भारतीय अधिकारी भी अमेरिका के सुरों में गाते नजर आते हैं।

चिंतन-मनन

क्यों कहते हैं विष्णु भगवान को नारायण

भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं। इनमें एक प्रमुख नाम है नारायण। फिल्मों, टीवी सीरियल या रामलीला में आपने देखा होगा कि नारद मुनि भगवान विष्णु को नारायण नाम से पुकारते हैं। इस नाम का धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। इस एक नाम में सृष्टि का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। इसलिए शास्त्रों में अधिकांश स्थानों पर विष्णु भगवान को नारायण नाम से संबोधित किया गया है। हिन्दू धर्म में अठारह पुराणों का वर्णन मिलता है। इन अठारह पुराणों में विष्णु पुराण एक है। इस पुराण में सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। इसी प्रम में बताया गया है किस प्रकार विष्णु भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल यानी पाताल लोक से उठाकर जल के मध्य में स्थित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सत्व, रज और तम गुणों से असुर, देव, राक्षस, यक्ष, मनुष्य, सर्प एवं अन्य जीव-जन्तुओं की रचना की। विष्णु पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के समाप्ति के समय सब कुछ जल में समा जाता है और संपूर्ण ब्रह्माण्ड अंधकारमय हो जाता है। भगवान विष्णु चिर निद्रा में जल में शयन करते हैं। देवताओं का दिन आरंभ होने पर भगवान विष्णु फिर से सृष्टि की रचना करते हैं और ब्रह्मा एवं शिव की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। भगवान विष्णु प्रथम नर रूप में व्यक्त होते हैं। इसलिए शास्त्रों में इन्हें आदिपुरुष कहा गया है। आदि पुरुष विष्णु का निवास यानी आवन नार यानी जल है इसलिए भगवान विष्णु को नारायण नाम से संबोधित किया जाता है।



सनत जैन

पिछले एक दशक में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठ रहे हैं। संविधान ने न्यायपालिका को कारप्रै बनावकर सर्वोच्च स्थान दिया है। कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका का संवैधानिक नियंत्रण, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण, कानून और नियमों का राज, सभी के लिए समान अवसर यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। संवैधानिक संस्थाएँ अपने दायित्व का सही ढंग से निवाह कर रही हैं, या नहीं। इस पर नियंत्रण रखने की मूल जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। गणतंत्र के 76वें वर्ष में खड़े होकर जब हम देखते हैं, तो वर्तमान की तस्वीर



कालिलाल मांडेत

लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि नागरिक चेतना का जीवन्त उत्सव है, और इस उत्सव की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति मतदान के माध्यम से होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहाँ करोड़ों लोग अपनी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और सपनों को मतपत्र के जरिए अभिव्यक्त करते हैं, वहाँ मतदाता की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है। इसी भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिन न केवल भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की याद दिलाता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य के प्रति सजग करने का भी अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। इसके पीछे निर्वाचन आयोग का स्पष्ट उद्देश्य था कि देश के हर पात्र नागरिक को मतदाता सूची में शामिल किया जाए और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। यह संयोग नहीं बल्कि एक सार्थक प्रतीक है कि 25 जनवरी को ही वर्ष 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तभी से यह दिन लोकतंत्र और चुनावी भागीदारी के उत्सव के रूप में संस्थागत रूप ले चुका है। आज यह आयोजन देश के कोने-कोने में, मतदान केंद्रों से लेकर जिला और राज्य मुख्यालयों तक, लाखों स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मतदान एक शक्तिशाली साधन है, जिसके माध्यम से नागरिक शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मतधिकार ने भारत के लोकतंत्र

पहले जैसी स्पष्ट और भरोसेमंद नजर नहीं आती है। पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ा है। जिस तरह के निर्णय आ रहे हैं, और टिप्पणियाँ हो रही हैं, उसको लेकर न्यायपालिका के उपर नागरिकों का दिन प्रतिदिन विश्वास घटता चला जा रहा है। बीते वर्षों में कई ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं, जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम बनाम सरकार का टकराव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों की ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट में मनमाने तरीके से न्यायाधीशों की बेंच में मामलों की सुनवाई संवैधानिक पीठों के गठन में देरी, महत्वपूर्ण याचिकाओं को वर्षों तक लंबित रखना, राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की सुनवाई वर्षों तक लंबित रखने, आधे-अधूरे निर्णय देना, आदेश के स्थान पर टिप्पणियाँ करना। यह सब इस बात का संकेत देते हैं। न्यायिक व्यवस्था में विचारधारा सरकार का दबाव और भेदभावपूर्ण निर्णय देने का चलन बढ़ा है। सरकार मनमाने निर्णय ले रही है। न्यायपालिका कई मामलों में अपेक्षित निर्णय नहीं ले रही है। न्यायपालिका सरकार के प्रति वह कठोरा नहीं दिखा रही, जो संविधान और कानून नियम के अनुसार जरूरी है। नागरिकता कानून, अनुच्छेद 370, चुनावी बांड, जांच एजेंसियों की मनमानी

कार्यवाही, नागरिकों की धार्मिक राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर न्यायिक सक्रियता की धीमी गति ने न्यायपालिका के प्रति नागरिकों के विश्वास को कमजोर किया है। नागरिकों की यह धारणा बनने लगी है, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का दबाव बढ़ गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मनमाने तरीके से ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फैसलों को लेकर सरकार का अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ता जा रहा है। जिसके कारण हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अलग लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सबसे चिंताजनक आरोप न्यायपालिका पर यह लगा रहा है, कि अब ह्र्दअमीरों के लिए अलग न्याय और गरीबों के लिए अलग न्यायह की स्थिति बनती जा रही है। जमानत के मामलों में असमानता, धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण फैसले, वर्षों से जेलों में बंद विचाराधीन कैदी, प्रभावशाली आरोपियों को त्वरित राहत मिलने, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, एसआईआर मामले की सुनवाई में तारीख पर तारीख के बीच बिहार विधानसभा के चुनाव हो जाना, इस तरह के सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। जिससे आम नागरिकों एवं न्यायविदों के मन में न्याय के प्रति अविश्वास देखने को मिल रहा है। न्यायपालिका को सरकार का संरक्षण मिलने और बदले में सरकार के हितों के प्रति नरमी दिखाने के कई फैसलों की चर्चा लोकतंत्र

के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस स्थिति का सीधा प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ रहा है। न्यायपालिका पर विश्वास कमजोर होता है, तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका के ऊपर है। यही लोगों के लिए अंतिम विश्वास के रूप में बना हुआ था जो अब खंडित हो रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है, कि नागरिकों का विश्वास न्यायपालिका के प्रति कैसे बना रहे? इसके लिए न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी है। न्यायाधीशों और न्यायालयों को वास्तविक संरक्षण प्राप्त हो, नियुक्तियों और तबादलों में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। संवेदनशील मामलों में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। गरीब और वंचित वर्ग के लिए त्वरित संवेदनशील न्याय की व्यवस्था मजबूत की जाए। न्यायाधीशों के आचरण में प्रदर्शित हो। न्यायपालिका के फैसलों में स्पष्टता हो। सुप्रीम कोर्ट पूर्व में दिए गए निर्णयों एवं संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए निर्णयों का वर्तमान न्यायाधीश समान करें। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसले दिए जा रहे हैं, वह स्पष्ट हों, फैसला संविधान कानून और नियम के अनुसार किए गए हैं। यह परीक्षित हो। न्यायपालिका की ताकत उसकी साख में है। न्यायपालिका की साख कमजोर हुई, तो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा संकट में पड़ जाएगा।

लोकतंत्र की धड़कन राष्ट्रीय मतदाता दिवस और जागरूक नागरिक की भूमिका

को एक मजबूत आधार प्रदान किया है। इसके बावजूद यह एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी देश के कई हिस्सों में मतदान प्रतिष्ठत अपेक्षाकृत कम रहता है। सामाजिक संकोच, राजनीतिक उदासीनता, जानकारी का अभाव और कुछ विशिष्ट परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो नागरिकों को मतदान से दूर रखती हैं। यही कारण है कि सहभागी लोकतंत्र की व्यापक प्रक्रिया कहीं-कहीं कमजोर पड़ती नजर आती है। भारत निर्वाचन आयोग इस चुनौती को गंभीरता से लेते हुए समय-समय पर कई पहल करता रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और इसके साथ जुड़ा व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी कार्यक्रम, जिसे एसडब्ल्यूईईपी के नाम से जाना जाता है, इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का मूल मंत्र है कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। इसके अंतर्गत युवाओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और हाशिए पर मौजूद वर्गों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाता पंजीकरण को प्रोत्साहित करना, उसे सरल बनाना और अधिकतम करना है, विशेष रूप से नए मतदाताओं के लिए। यह दिन मतदाताओं को समर्पित है और इसका उपयोग चुनावी प्रक्रिया में सूचित और जिम्मेदार भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र प्रदान करना, उन्हें मतदान की प्रक्रिया समझाना और उनके भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों का बीजारोपण करना इस दिन की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है। इस अवसर पर मतदाताओं की शपथ की अवधारणा भी विशेष महत्व रखती है। यह शपथ नागरिकों को याद दिलाती है कि लोकतंत्र में उनका विश्वास केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि उनके आचरण में भी परिलक्षित हो। शपथ के माध्यम से मतदाता यह संकल्प लेते हैं कि वे स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा बनाए रखेंगे और धर्म, जाति, समुदाय, भाषा या किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना निर्भीक होकर मतदान करेंगे। यह सामूहिक शपथ नागरिक जिम्मेदारी और नैतिक भागीदारी की भावना को सार्थक करती है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन में जन जागरूकता और सहभागिता पर विशेष बल दिया जाता है। वर्ष 2021 में आयोजित 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन कोविड-19 की चुनौती के बीच भौतिक और आभासी कार्यक्रमों के संयोजन के रूप में किया गया। इस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का भाग लिया। उस वर्ष का विषय था अपने मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित बनाना, जो महामारी के दौर में सुरक्षित और नैतिक चुनावों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डिजिटल युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस अवसर पर कई अभिनव पहलें भी शुरू कीं। डिजिटल मतदाता पहचान पत्र यानी ई-ईपीआईसी की शुरुआत इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। अब मतदाता अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं या स्वयं प्रिंट कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जैसी सुविधाओं ने मतदाता सेवाओं को और अधिक सुलभ बना दिया है। इसी क्रम में हॉरेडियो हेल्थो वोटर्स जैसी 24 घंटे चलने वाली डिजिटल रेडियो सेवा की शुरुआत भी की गई, जिसका उद्देश्य विभिन्न भाषाओं में गीतों, नाटकों, चर्चाओं और पॉडकास्ट के माध्यम से मतदाता जागरूकता फैलाना है। यह पहल देशाती है कि लोकतांत्रिक शिक्षा अब केवल पुस्तकों या सभाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए जन-जन तक पहुँच रही है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उत्कृष्ट चुनावी प्रक्रियाओं के लिए अधिकारियों, सरकारी विभागों और मीडिया संस्थानों को सम्मानित करना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा बन चुकी है। इससे न केवल प्रशासनिक तंत्र का मनोबल बढ़ता है, बल्कि चुनावी व्यवस्था में निरंतर सुधार और नवाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। चुनाव आयुक्तों के अनुसार, इन आयोजनों का एक प्रमुख उद्देश्य नए और युवा मतदाताओं को प्रेरित करना है, ताकि वे स्वयं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा समझें।

वर्ष 2026 में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस उसी उत्साह और उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन विशेष रूप से छात्रों और पहली बार मतदान करने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के युवा ही कल के नीति-निमाता और नेतृत्वकर्ता होंगे। यदि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे, तभी लोकतंत्र मजबूत और जीवन्त रह पाएगा। छात्रों के लिए यह दिन एक समझने का अवसर है कि एक वोट किस प्रकार नीतियों, सरकारों और देश के भविष्य को दिशा दे सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप होते हैं। कहीं जागरूकता रैलियाँ निकलती हैं, कहीं मुक्कड़ नाटक और लोक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोकतांत्रिक शिक्षा दी जाती है। स्कूलों और कॉलेजों में वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर युवाओं को लोकतांत्रिक विमर्श से जोड़ा जाता है। शहरी क्षेत्रों में डिजिटल माध्यमों पर जोर होता है, तो ग्रामीण इलाकों में प्रत्यक्ष संवाद और सामुदायिक सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि लोकतंत्र को आत्मसात करने की एक सतत प्रक्रिया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। यदि नागरिक सजग, सूचित और नैतिक होंगे, तो लोकतंत्र स्वतः सशक्त होगा। मतदान केवल एक दिन की क्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अंततः, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने मतधारिक का उपयोग पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। क्या हम केवल दर्शक बनकर रह गए हैं या सचमुच सहभागी नागरिक हैं। जब हर मतदाता यह समझ लेगा कि उसका एक वोट भी बदलाव की क्षमता रखता है, तभी लोकतंत्र अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इसी जागरूकता की मशाल है, जो हर वर्ष हमें हमारे लोकतांत्रिक कर्तव्यों की याद दिलाती है और एक बेहतर, अधिक सहभागी भारत की ओर अग्रसर करती है।

संक्षिप्त समाचार

रवांडा में एआई तकनीक से विलनिक सुधार की शुरुआत

किगाली, एजेंसी। रवांडा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित तकनीक का परीक्षण शुरू करने का फैसला किया है। यह योजना गेट्स फाउंडेशन और ओपनएआई की साझेदारी से चलाई जा रही है, जिसके तहत देश के 50 से ज्यादा स्वास्थ्य विलनिकों में इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद डॉक्टरों और नर्सों के काम को आसान बनाना और मरीजों को जल्दी व सही इलाज दिलाना है। रवांडा में एक स्वास्थ्य कर्मी पर करीब 1,000 मरीजों का बोझ है, जबकि दुनिया में आदर्श अनुपात 4 स्वास्थ्य कर्मी प्रति 1,000 मरीज माना जाता है। ऐसे में एआई तकनीक से मरीजों की जानकारी संभालने, रिपोर्ट तैयार करने और इलाज से जुड़े फैसलों में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह तकनीक डॉक्टरों की जगह नहीं लेगी, बल्कि उनके काम को और मजबूत बनाएगी। गेट्स फाउंडेशन और ओपनएआई ने इस परियोजना के लिए दो साल में 50 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। बिल गेट्स ने कहा कि गरीब देशों में, जहां स्वास्थ्य संसाधन कम हैं, वहां एआई एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे इलाज तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी और स्वास्थ्य असमानता कम होगी। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि यह तकनीक अंग्रेजी भाषा पर आधारित है, जबकि रवांडा में अधिकतर लोग किन्यारवांडा भाषा बोलते हैं। डिजिटल विशेषज्ञ ऑडोसे नियोकुरु ने कहा कि अगर एआई स्थानीय भाषा में काम नहीं करेगा तो इलाज में दिक्कत आ सकती है। सरकार और तकनीकी कंपनियां अब इसे किन्यारवांडा भाषा में विकसित करने पर काम कर रही हैं।

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, विदेशी सहायता पर सख्ती और बढ़ेगी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने विदेशी सहायता से जुड़े नियमों को और सख्त करने का फैसला किया है। अब अमेरिका उन संस्थाओं को भी मदद नहीं देगा जो गर्भपात सेवाओं के साथ-साथ जेंडर आइडेंटिटी या डीईआई (डायरेक्टि, इक्विटी और इन्क्लूजन) कार्यक्रमों को बढ़ावा देती हैं। पहले यह रोक केवल गर्भपात से जुड़ी सेवाओं तक सीमित थी। इस नीति को मेक्सिको सिटी पॉलिसी कहा जाता है, जिसे सबसे पहले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने लागू किया था। ट्रंप प्रशासन ने इसके दायरे को और बढ़ा दिया है। नए नियमों से करीब 30 अरब डॉलर की विदेशी सहायता प्रभावित हो सकती है, जो अंतरराष्ट्रीय संगठनों और एजेंसियों को दी जाती है। मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे दुनिया के गरीब देशों में महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को मिलने वाली जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। ह्यूमन राइट्स कैंपेन की अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला राजनीति को इंसानी जीवन से ऊपर रखता है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल उन नीतियों पर नहीं होना चाहिए जो उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं।

दक्षिण अफ्रीका में स्कूल बस हादसा, मौत का आंकड़ा 14 पहुंचा

गाउतेंग, एजेंसी। दक्षिण अफ्रीका के गाउतेंग प्रांत में हुए दर्दनाक स्कूल बस हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। गुुववार को दो किशोर छात्राओं की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा सोमवार सुबह उस समय हुआ था जब एक निजी मिनीबस 16 छात्रों को स्कूल छोड़ने जा रही थी और उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई थी। हादसे में मौके पर ही 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके अलावा बस चालक और ट्रक में बैठे एक यात्री सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन अब भी दो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मृतक छात्राएं काफी गंभीर हालत में थीं और उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस मामले में बस चालक अयांडा दलदला पर पहले लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया गया था।

अमेरिका में भीषण बर्फ़ीले तूफान की चेतावनी, करोड़ों लोग अलर्ट पर

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के कई राज्यों में एक बेहद खतरनाक बर्फ़ीला तूफान आने की चेतावनी दी गई है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक करीब 10 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की मौसम चेतावनी के दायरे में हैं। यह तूफान न्यू मैक्सिको से लेकर कैरोलाइना तक और फिर पूर्वी तट के बड़े शहरों तक असर डाल सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि कई इलाकों में आधा इंच तक बर्फ़ जम सकती है, जिससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और लंबे समय तक बिजली गुल रहने का खतरा है। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहरों में एक फुट तक बर्फ़ गिरने की आशंका जताई गई है। तूफान के कारण हवाई अड्डों पर उड़ानें रद्द हो सकती हैं और सड़कों पर यात्रा बेहद खतरनाक हो जाएगी।

अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से तोड़ा नाता, कोविड विफलताओं का लगाया आरोप

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका ने आपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से अपनी सदस्यता खत्म कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन किए गए वादे को पूरा करने के तहत लिया गया है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर ने एक संयुक्त बयान में बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के जरिए यह वाक्य सी लागू की गई। इस फैसले का उद्देश्य अमेरिका को डब्ल्यूएचओ की ‘पाबंदियों’ से मुक्त करना और कोविड-19 महामारी के दौरान हुई विफलताओं से हुए नुकसान की भरपाई करना है। बयान में कहा गया,

‘आज अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से खुद को अलग कर लिया है, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले दिन वादा किया था। यह कदम कोविड-19 के दौरान डब्ल्यूएचओ की नाकामियों के जवाब में उठाया गया है, जिनका खामियाजा अमेरिकी जनता को भुगताना पड़ा। ’

प्रशासन ने डब्ल्यूएचओ पर अपने मूल उद्देश्य से भटकने और अमेरिकी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। बयान में कहा गया कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ का संस्थापक सदस्य और सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता रहा है, इसके बावजूद संगठन ने अमेरिका के हितों की अनदेखी की। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि डब्ल्यूएचओ ने राजनीतिक

अमेरिका में 5 साल के बच्चे को हिरासत में लिया

मिनेसोटा, एजेंसी। मिनेसोटा के कोलंबिया हाइट्स में मंगलवार को इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंट्स ने एक 5 साल के बच्चे लियाम कोनेजो रामोस को पिता के साथ हिरासत में लिया गया। दोनों को टेक्सस के इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर भेजा गया है। लियाम की स्कूल सुपरिटेंडेंट जेना स्टेनविक ने बताया, ‘एजेंट्स ने चलती गाड़ी से बच्चे को उतारा। फिर उन्होंने उसे घर का दरवाजा खटखटाने को कहा, ताकि पता चले कि अंदर कोई है या नहीं।’ जेना ने इसे 5 साल के बच्चे का इस्तेमाल करना बताया। गिरफ्तारी के डर से पिता ने मां को दरवाजा खोलने से मना किया। हालांकि कुछ देर बाद माता-पिता ने अपने बच्चे को घर के अंदर लाने की मंशा से दरवाजा खोला, तभी बाहर मौजूद एजेंट्स ने पिता को गिरफ्तार किया। वहीं बच्चे को घर में मौजूद दूसरे लोगों को सौंपने से इनकार कर उसे भी अपने साथ ले गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिनियापोलिस लीडर्स से मुलाकात के दौरान घटना पर बात की। उन्होंने कहा कि ‘बच्चा सिर्फ डिटेन हुआ है, गिरफ्तार नहीं।’ वेंस ने कहा कि एजेंट्स बच्चे को ठंड में छोड़ नहीं सकते थे और गैरकानूनी व्यक्ति को गिरफ्तार करना जरूरी है।

6 हफ्तों में मिनेसोटा में 3,000 गिरफ्तारियां हुईं, इनमें 400 बच्चे: लियाम अपने स्कूल जिले का चौथा छात्र है जिसे दृष्टि ने हिरासत में लिया है। स्कूल अधिकारियों और परिवार के

जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भंग की संसद, 8 फरवरी को होंगे मध्यावधि चुनाव

टोक्यो, एजेंसी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने शुक्रवार को संसद के निचले सदन को भंग कर दिया, जिससे देश में 8 फरवरी को मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। तकाइची ने यह फैसला केवल तीन महीने के कार्यकाल के बाद लिया है। अक्टूबर में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई तकाइची को अब तक लगभग 70 प्रतिशत की ऊंची लोकप्रियता मिली है। माना जा रहा है कि वह इसी लोकप्रियता का लाभ उठाकर सत्तारूढ़ दल की स्थिति मजबूत करना चाहती हैं, जिसे हाल के वर्षों में भारी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि, संसद भंग होने से उस बजट पर मतदान टल गया है, जिसका उद्देश्य कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा देना और बढ़ती महंगाई से निपटना था। 465 सदस्यीय निचले सदन के भंग होने के साथ ही 12 दिनों का चुनाव प्रचार अभियान शुरू होगा, जिसकी औपचारिक शुरुआत मंगलवार से होगी। प्रधानमंत्री तकाइची ने कहा कि वह चाहती हैं कि जनता तय करे कि उन्हें प्रधानमंत्री

बने रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस चुनाव को अपने राजनीतिक भविष्य से जोड़ रही हैं। सख्त रुख वाली रूढ़िवादी नेता तकाइची अपने पूर्ववर्ती शिगेरु इशिबा से अलग नीतियों को सामने रखना चाहती हैं। उनके एजेंडे में ज्यादा सरकारी खर्च, सैन्य ताकत में इजाफा और कड़ी आब्रजन नीति शामिल है, ताकि जापान को ‘मजबूत और समृद्ध’ बनाया जा सके।

युवाओं में लोकप्रिय तकाइची की छवि : हालांकि तकाइची की छवि युवा मतदाताओं में लोकप्रिय है, लेकिन सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) अभी भी राजनीतिक फाड़ों कोटाले के असर से उबर रही है। इसके चलते कई पारंपरिक मतदाता उभरती दक्षिणपंथी विपक्षी पार्टियों की ओर रुख कर चुके हैं। प्रधानमंत्री का लक्ष्य इस चुनाव के जरिए निचले सदन में मजबूत बहुमत हासिल करना है, ताकि उनकी सरकार बिना विपक्ष पर निर्भर हुए अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सके।

डोनाल्ड ट्रंप के दामाद संग रात भर चली पुतिन की मीटिंग, जेलेंस्की बोले- हम तो रूस की दया पर हैं

मॉस्को, एजेंसी। वैश्विक राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। एक तरफ दवाोंस में डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान किया तो वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में पूरी रात वार्ता चलती रही। लंबे समय बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटक्रॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर रातभर रूस के राष्ट्रपति भवन क्रैमलिन में रहे। यहां पर यूक्रेन के साथ 4 सालों से चली आ रही जंग खत्म करने को लेकर मीटिंग हुई। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे और उन्होंने साफ कर दिया कि यह समझौता तभी संभव है, जब उसके कब्जे वाले इलाकों को मान्यता दी जाए और वहां से यूक्रेन अपना किनारा कर ले। हालांकि यूक्रेन के



लिए ऐसा स्वीकार करना आसान नहीं होगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ऐसा कई बार कह चुके हैं कि हम अपने इलाके नहीं छोड़ेंगे। यह मीटिंग ऐसे

समय में हुई है, जब गुरवार को ही वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि रूस के हमले के जवाब में यूरोप या अमेरिका से हमें मदद नहीं मिल रही है। उनका कहना था कि हालात ऐसे हैं कि हमें व्लादिमीर पुतिन की दया पर छोड़ दिया गया है। क्रैमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि हमने मीटिंग में साफ कर दिया है कि जो इलाके रूस के नियंत्रण में हैं, उन्हें मान्यता दी जाए। वहीं यूक्रेन को इससे सख्त आपत्ति है। जेलेंस्की का कहना है कि पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर रूस का अवैध कब्जा है और हम इसे स्वीकार नहीं करते। पुतिन बोर्ड ऑफ पीस के लिए भी तैयार, मदद भी देंगे जेलेंस्की ने

गुरवार को दावोस में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के दौरान भी कहा था कि पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर रूस ने कब्जा जमा रखा है। इसका मसला अभी हल नहीं हुआ है और शांति प्रस्ताव लागूमा तैयार है। इस बीच शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात में एक मीटिंग होगी है। इसमें रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इस मीटिंग में गाजा को लेकर बने बोर्ड ऑफ पीस की भी बात हुई। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं और एक अरब डॉलर की रकम भी देंगे। उन्होंने कहा कि यह रकम उन संपत्तियों से ले ली जाए, जो रूस की हैं और उन्हें अमेरिका ने सीज कर रखा है।

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के दो वरिष्ठ डेमोक्रेट लॉमैकर्स ने टेक दिग्गज कंपनी मेटा और गूगल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसदों का कहना है कि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) और उसकी एजेंसी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) इन प्लेटफॉर्मस पर ऐसे विज्ञापन चला रही है, जिनमें श्वेत राष्ट्रवादी विचारधारा और भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउस जूडिशियरी कमेटी की उपध्यक्ष बेका बैलेंट और इमिग्रेशन प्रवर्तन की निगरानी करने वाली उपसमिति की प्रमुख, भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल ने मेटा और गूगल के सीईओ को अलग-अलग पत्र भेजे हैं। इन पत्रों में उन्होंने मांग की है कि डीएचएस के साथ डिजिटल विज्ञापन से जुड़ी सभी साझेदारियां तुरंत खत्म की जाएं और यह बताया जाए कि कंपनियों के बीच समझौते का दायरा और अवधि क्या



है। सांसदों का कहना है कि आईसीई इन विज्ञापनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान के लिए कर रही है। इसके तहत मिनियापोलिस, शिकागो, पोर्टलैंड और न्यू ऑर्लीयन्स जैसे शहरों में हजारों नए अधिकारियों को तैनात करने की योजना है। आरोप है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए भर्ती मानकों में भी ढील दी गई है। पत्रों में दावा किया गया है कि आईसीई ने ऐसे विज्ञापन चलाए हैं, जिनमें ‘श्वेत राष्ट्रवादी प्रेरित प्रचार’

ट्रंप का कनाडा को झटका: ‘बोर्ड ऑफ पीस’ में शामिल होने का न्यौता वापस लिया

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को अपने नए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया है। यह कदम उत्तर अमेरिका के दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रही ताजा तनातनी के बीच उठाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्वािटर पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को संबोधित करते हुए लिखा कि पीस बोर्ड ने कनाडा को भेजा गया अपना निमंत्रण वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि, पोस्ट में ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि उन्होंने कनाडा को दिया गया यह निमंत्रण क्यों रद्द किया। वापस लेने के पीछे की वजह को लेकर उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। बता दें कि बुधवार को, ट्रंप ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि ‘कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है।’ कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि कनाडा अपने अस्तित्व के लिए अमेरिका पर निर्भर है। कार्नी ने कहा, ‘कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक शानदार साझेदारी बनाई है। अर्थव्यवस्था में, सुरक्षा में और समृद्ध सांस्कृतिक आदान-प्रदान में, लेकिन कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा नहीं है। कनाडा इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि हम कनाडाई हैं। विषय में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की शुरुआत की है। इसमें

शामिल होने के लिए ट्रंप ने दुनिया के लगभग 60 देशों को न्यौता भेजा। इजरायली मीडिया के अनुसार, 60 में से दुनिया के 25 देशों ने ट्रंप के न्यौते को स्वीकार कर लिया है। बोर्ड ऑफ पीस में अब तक इजरायल, बहरीन, मोरक्को, अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, पाकिस्तान, पराग्वे, कतर, सऊदी अरब, तुर्किए, संयुक्त अरब अमीरात, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, मिस्र, वियतनाम और मोंगोलिया शामिल हुए। आठ इस्लामिक देशों ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्यौता स्वीकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाजा में इजरायल-हमास सीजफायर समझौते के दूसरे फेज के तहत घोषित बोर्ड में शामिल होने के लिए बुलाया था। हालांकि, भारत की तरफ से फिलहाल इसपर कोई फैसला सामने नहीं आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल इसपर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी, स्वीडन, नार्वे और कई दूसरे बड़े देशों ने इस साईनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया। इसके साथ ही जर्मनी, इटली, पेरग्वे, रूस, स्लोवेनिया, तुर्किए और यूक्रेन जैसे कई देशों ने इस न्यौते पर कोई वादा नहीं किया है। बोर्ड में शामिल सदस्य देशों का कार्यकाल तीन साल तक सीमित होगा, और स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए कथित तौर पर 1 बिलियन डॉलर का भुगतान करना होगा।

गूगल और मेटा से विवादित विज्ञापन हटाने की मांग, अमेरिकी सांसदों ने उठाए सवाल

में ऐसे विज्ञापनों पर करीब 30 लाख डॉलर खर्च किए गए। बताया गया कि पिछले साल आईसीई ने मेटा और गूगल पर कुल मिलाकर लगभग 58 लाख डॉलर के विज्ञापन चलाए। सांसदों ने एक इंस्टाग्राम विज्ञापन का उदाहरण भी दिया, जिसमें लिखा था, ‘हमारा घर फिर से हमारा होगा।’ सांसदों का कहना है कि यह नारा अक्सर कट्टरपंथी और नव-नाजी समूहों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सांसदों ने यह भी आरोप लगाया कि आईसीई ने भर्ती के नियमों में ढील दी है, जैसे उम्र सीमा हटाना, 50,000 डॉलर तक का साईनिंग बोनस देना और नए भर्ती अधिकारियों को बिना पर्याप्त प्रशिक्षण के मैदान में उतारना। सांसदों ने कहा कि मेटा और गूगल से यह भी पूछा कि उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन कैसे चलने दिए गए, जिनमें दोनों कंपनियों की नीतियां नफरत और भेदभावपूर्ण सामग्री के खिलाफ हैं।

अमेरिकी धरती पर रामायण की गूंज : मैरीलैंड के प्रतिनिधियों ने देखी विशेष प्रदर्शनी

एनापोलिस, एजेंसी। एशिया और उससे आगे रामायण के प्रसार पर आधारित एक दिवसीय प्रदर्शनी अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट असेंबली बिल्डिंग में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में स्टेट लॉ मेकर, राजनयिक और समाज के कई प्रमुख लोग शामिल हुए। यह आयोजन एनापोलिस पॉर्सर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे। कार्यक्रम में मैरीलैंड के कई प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। प्रतिनिधि वू चाओ ने कहा कि यह प्रदर्शनी दिखाती है कि संस्कृति कैसे अलग-अलग देशों और पृष्ठभूमियों के लोगों को जोड़ती है। उनके अनुसार ऐसी सांस्कृतिक पहल लोगों के बीच समझ बढ़ाती है और राजनीति में दिखने वाले मतभेदों को कम करने का काम करती है। चाओ ने कहा, ‘यह एक पेसी संस्कृति है जो लोगों को जोड़ती है और विविधता प्रदान करती है और वास्तव में विभिन्न पृष्ठभूमियों के बीच समझ को बढ़ाती है।’ प्रतिनिधि हैरी भंडारी ने रामायण की नैतिक शिक्षाओं पर बात करते हुए कहा कि यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शक है। उन्होंने बताया कि रामायण हमें चरित्र, त्याग, पारिवारिक मूल्यों, विनम्रता और अहंकार से बचने की सीख देती है। आज के समय में, जब समाज कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, ये शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं।



प्रदर्शनी मास्क रोजर सेना में रह चुके हैं और एशिया के कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी ने उनके अनुभवों की याद दिला दी। उनके अनुसार, ‘हमारे बीच मतभेदों की तुलना में अधिक समानताएं हैं। साझा

एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क की उड़ानें कीं रद्द, अमेरिका में भीषण विंटर स्टॉर्म का खतरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में संभावित भीषण और ऐतिहासिक विंटर स्टॉर्म को देखकर एयर इंडिया ने 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के नेवार्क से आने-जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने यह फैसला यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया है। एयर इंडिया द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइसरी के अनुसार, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह से सोमवार तक भारी बर्फबारी, तेज ठंडी हवाएं और अत्यधिक ठंड पड़ने की आशंका है। ऐसे हालात में हवाई संचालन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। एयरलाइन ने कहा है कि 'यात्रियों और क्रू की सुरक्षा, सुविधा और भलाई को ध्यान में रखते हुए 25 और 26 जनवरी को न्यूयॉर्क और नेवार्क से संचालित होने वाली सभी उड़ानें रद्द की जा रही हैं।' यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट की ताजा स्थिति जानने के लिए एयर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप या कस्टमर केयर से संपर्क बनाए रखें। साथ ही, टिकट रिफंड और रीक्रेडिंग से जुड़ी जानकारी भी वहीं उपलब्ध है। उधर, अमेरिका इस समय एक रिकॉर्ड तोड़ विंटर स्टॉर्म की चपेट में है। नेशनल वेदर सर्विस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यह तूफान सेंट्रल प्लेन्स से लेकर नॉर्थ-ईस्ट तक करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। भारी बर्फबारी, बर्फौली बारिश और खतरनाक ठंड के चलते कई इलाकों में सड़कें बंद होने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यात्रा व्यवस्था पूरी तरह ठप होने की आशंका जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें और आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें।

एमपी में रेल हादसा : मक्सी स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी, दो हिस्सों में बंटी

शाजापुर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जब मक्सी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी अचानक पटरी से उतर गई। हादसे में मालगाड़ी दो हिस्सों में बंट गई, हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा मेन लाइन की पटरी टूटने के कारण हुआ। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी का संतुलन बिगड़ते ही उसके कई डिब्बे पटरी से उतर गए और जमीन में धंस गए। गंभीरत यह रही कि घटना के समय इस रूट से कोई यात्री ट्रेन नहीं गुजर रही थी, अन्यथा नुकसान कहीं अधिक हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। साथ ही ट्रैक की मरम्मत का कार्य भी तत्काल शुरू कर दिया गया। हालांकि जब मीडिया ने अधिकारियों से जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने जांच पूरी होने तक कोई आधिकारिक बयान देने से परहेज किया। हादसे के बाद मेन लाइन बंद होने से कई यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। कुछ ट्रेनों को रोक दिया गया, जबकि एक लाइन को आंशिक रूप से चालू कर ट्रेनों को धीमी गति से निकाला गया। स्टेशन प्रबंधन के अनुसार प्रथम दृष्टया यह घटना ट्रैक की तकनीकी खराबी के कारण प्रतीत हो रही है। घटना की विस्तृत जांच के लिए उच्चतम से रेलवे अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंच रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

केरल में भाजपा ने लोकपाल की नियुक्ति का किया विरोध

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल में लोकपाल की नियुक्ति का विरोध कर इस वैधानिक रूप से गलत बताया है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और महासचिव वकील एस. सुरेश ने लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर से मुलाकात कर याचिका सौंपकर कैबिनेट द्वारा जरिस्ट (रिटार्ड) बाबू मैथ्यू पी. जोसेफ़को लोकपाल नियुक्त करने के फैसले पर आपत्ति जता दी। भाजपा ने केरल लोकायुक्त अधिनियम- 1999 की धारा 5 (3) का हवाला देकर कहा कि यह प्रावधान किसी पूर्व लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को किसी सरकारी या स्वायत्त निकाय में पद संभालने से रोकता है। भाजपा का दावा है कि लोकपाल एक सरकारी पंष्ठ से वेतन पाने वाला वैधानिक पद है और इस पर मनमानी व्याख्या नहीं की जा सकती। केरल बीजेपी ने चेतावनी दी कि इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाली कोई भी नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य होगी और न्यायिक जांच के दायरे में आएगी। भाजपा ने कहा कि लोकपाल जैसी संस्थाओं की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि ये संस्थाएं जमीनी स्तर पर शासन की निगरानी करती हैं और जनता का विश्वास बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। पार्टी ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वह अपने संवैधानिक विवेक का उपयोग कर कैबिनेट के फैसले को वैधानिक आधार पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजें। राज्यपाल कार्यालय ने 'एक्स' पर भी मुलाकात की जानकारी देकर लिखा कि भाजपा नेताओं ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देकर लोकपाल नियुक्ति का विरोध किया।

डोडा हादसे में चनौली का जवान जौबनप्रीत शहीद, सीएम मान ने जताया दुख

चंडीगढ़ (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना का वाहन खाई में गिरने से 10 जवान शहीद हो गए थे। इस हादसे में पंजाब के रोपड़ जिले के जांच चनौली के रहने वाले जवान जौबनप्रीत सिंह (23) भी शहीद हो गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जौबनप्रीत सिंह की शहादत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शहीद जौबनप्रीत सिंह की शहादत पर पूरे प्रदेश को गर्व है। सीएम मान ने शहीद जवान के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश के प्रति उनके साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम भगवंत मान ने एक्स पर लिखा- बीते दिनों जम्मू-कश्मीर के डोडा में जवानों से भरी एक बस के गहरी खाई में गिर जाने से 10 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। उन शहीदों में जिला रोपड़ के गांव चनौली के जौबनप्रीत सिंह के शहीद होने की दुखद खबर मिली है। परिवार के प्रति गहरी संवेदना। देश के प्रति शहीद जवान के साहस को हम नमन करते हैं। इस कठिन घड़ी में सरकार शहीद के परिवार के साथ खड़ी है। परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। इस हादसे पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दुःख जताया। ताम्राम नेताओं ने शहीद जवानों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और यादगोले के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

नई जनगणना अधिसूचना में जाति के लिए कोई कॉलम नहीं: पवन खेड़ा

-विपक्ष हुआ हमलावर, कांग्रेस और सपा ने सरकार की नीयत पर उड़ा सवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में आगामी जनगणना को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद सियासी चमत्सासन तेज हो गया है। जनगणना की अधिसूचना में जाति का अलग कॉलम न होने को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों ने इसे जातिगत जनगणना को लेकर सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरे हुए कहा कि भाजपा जातिगत जनगणना की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में उससे पीछे हटती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, कि नई अधिसूचना में जाति के लिए कोई कॉलम नहीं है, जो सरकार के इरादों पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं, उसका ठीक उल्टा करते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा पहले बड़े-बड़े दावे



करती है, लेकिन फैसले लेने के समय बिना सोचे-समझे कदम उठाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा,

प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं तो यह मान लेना चाहिए कि व्यवहार में उसका उल्टा ही होगा।

पंजाब कांग्रेस में राट? राहुल गांधी की बैठक से दूरी के बाद नवजोत सिद्धू ने किया शायराना हमला

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब कांग्रेस के भीतर असंतोष के सुरू एक बार फिर तेज होते दिख रहे हैं। शशि थरूर के बाद अब पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के रुख को भी पार्टी नेतृत्व के प्रति नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस खींचतान की ताजा वजह बनी है राहुल गांधी द्वारा बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भविष्य की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि नवजोत सिंह सिद्धू को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया।

राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया। इस बैठक में प्रदेश के मौजूद और पूर्व कई दिग्गज पदाधिकारी शामिल हुए, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की गैर-मौजूदगी ने सियासी हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए। बैठक के ठीक अगले दिन शुक्रवार दोपहर बाद सिद्धू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया,

जिसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर चल रही चर्चाओं को और हवा दे दी है। इस वीडियो में नवजोत सिद्धू अपने चिर-परिचित शायराना अंदाज में अपनी बात कहते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बोल काफी गहरे थे। वीडियो में वे कहते हैं, 'जिसने आपको नहीं बुलाया, उसे दफा कीजिए, हर कोई आपके काबिल नहीं होता और कई बार अकेले रहना ही बेहतर होता है।' सिद्धू के इन शब्दों को राजनीतिक विश्लेषक सीधे तौर पर राहुल गांधी की बैठक में उन्हें नजरअंदाज किए जाने से जोड़कर देख रहे हैं। इसे नेतृत्व के प्रति एक मौन विरोध और कड़ा संदेश माना जा रहा है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स को पार्टी नेतृत्व से उनकी असहजता के संकेत के रूप में देखा गया था। अब सिद्धू के इस वीडियो ने यह संकेत दिया है कि कांग्रेस में आलमगमान और कुछ कड़ावर नेताओं के बीच खींचतान पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों को होगी 1 से 10 साल की जेल, जुर्माना भी लगेगा

-छह महीनों में देशभर में कुल 1,698 घटनाएं हुईं, 665 को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया। जुलाई से दिसंबर 2025 के बीच के आंकड़ों के मुताबक पिछले छह महीनों में देशभर में पत्थरबाजी की कुल 1,698 घटनाएं हुईं। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने इन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 665 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पत्थरबाजी की यह प्रवृत्ति न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएफ की जांच में सामने आया है कि पत्थरबाजों के निशाने पर सबसे ज्यादा बंद धारात एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें हैं। हालांकि इन आधुनिक ट्रेनों में बेड मजबूत शीट्सफर्स्ट क्लास लगाए गए हैं, लेकिन भारी पथराव के कारण ये भी टूट रहे हैं। वहीं, सामान्य यात्री ट्रेनों में खिड़की के शीशे टूटने से कई यात्रियों के घायल होने की खबरें हैं। रेलवे



ने उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है जहां ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं। इन क्षेत्रों में आरपीएफ की गश्त बढ़ा दी गई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज के साथ-साथ स्थानीय मुखबिरों की मदद ली जा रही है। रेलवे प्रशासन ने साफ कहा है कि यात्रियों की जान जोखिम में डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पकड़े गए आरोपियों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे चलाए जा रहे हैं। इन धाराओं के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर एक साल से लेकर 10

गणतंत्र दिवस परेड में गुंजेगी ऑपरेशन सिंदूर की धमक: शौर्य प्रदर्शन करेंगे राफेल-सुखोई विमान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर कर्तव्य पथ का आसमान भारतीय वायुसेना के अदम्य साहस और अत्याधुनिक मारक क्षमता का गवाह बनेगा। इस वर्ष फ्लाई पास्ट का मुख्य आकर्षण विशेष रूप से तैयार किया गया 'सिंदूर' फॉर्मेशन होगा। यह फॉर्मेशन पिछले वर्ष पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाले ऑपरेशन सिंदूर को सफलता का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक फॉर्मेशन में भारतीय वायुसेना के सात शक्तिशाली विमान शामिल होंगे, जिनमें 2 राफेल, 2 मिग-29, 2 सुखोई-30 और एक जैगुआर

फ़हटर जेट अपनी गर्जना से आसमान को गुंजायमान करेंगे।

भारतीय वायुसेना के अनुसार, इस बार फ्लाई पास्ट में कुल 29 विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इन्में 16 फाइटर जेट, 4 मालवाहक (ट्रांसपोर्ट) विमान और 9 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। परेड की शुरुआत में वायुसेना के चार एमआई-17 हेलीकॉप्टर ध्वज फॉर्मेशन में उड़ान भरेगे, जो राष्ट्रीय ध्वज के साथ-साथ थल सेना, नौसेना और वायुसेना के ध्वज लहराते हुए देश को गौरवन्वित करेंगे। इसके अतिरिक्त, वायुसेना के विमान प्रहार, गरुड़, अर्जुन, वरुणा, वज्रंग और विजय जैसे विभिन्न प्रभावशाली फॉर्मेशन में भी अपनी सटीक उड़ान का प्रदर्शन करेंगे।

गणतंत्र दिवस 2026 का आयोजन विशेष रूप से 'वंदे मातरम' के गौरवशाली 150 वर्षों को समर्पित किया गया है। पूरे समारोह पर राष्ट्रीय की स्पष्ट छाप दिखाई देगी और वायुसेना का बैंड इससे जुड़ी विशेष धुनें बजाकर देशप्रेम का संचार करेगा। परेड में अनुशासन और नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए वायुसेना की ओर से विशेष तैयारियों की गई हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित होने वाले श्रद्धांजलि समारोह में स्काइन लीडर हेमंत सिंह कन्यार गार्ड ऑफऑनर के कमांडर के रूप में वीर शहीदों को नमन करेंगे। कर्तव्य पथ पर ध्वजारोहण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट अश्विना ढॉकर निभाएंगी, जबकि स्काइन लीडर जगदेश

कुमार के नेतृत्व में वायुसेना का मार्चिंग दल अपनी सटीक कदमताल से दर्शकों का मन मोहेगा। फ्लाई पास्ट के समापन चरण में राफेल, सुखोई-30, सी-295, अपाचे और स्वदेशी एलसीएच (प्रचंड) जैसे विमान शामिल रहेंगे। इस बार की परेड में न केवल वायुसेना का अनुशासन और पेशेवर उत्कृष्टता दिखाई देगी, बल्कि तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भारत की आत्मनिर्भरता को भी दर्शाएगा। समारोह की भव्यता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत 100 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा पारंपरिक युद्ध-संगीत के साथ की जाएगी, जो कर्तव्य पथ पर शौर्य और संस्कृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगे।



शंकराचार्य अविमुक्तानंद और सरकार मिलकर करें सुलह, सतानत का न बनने दें मजाक

-रामगंजमंडी में कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने चले रहे विवाद पर दी दोनों पक्षों को सलाह

कोटा (एजेंसी)। शिक्षा नगरी कोटा इन दिनों भक्ति नगरी में तब्दील हो चुकी है। रामगंजमंडी में कथावाचक आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा के पहले ही दिन आस्था का सैलाब उमड़ा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से आयोजित इस गौ माता महोत्सव के पहले दिन धीरेंद्र शास्त्री ने न केवल धार्मिक उपदेश दिए। प्रयागराज में पालकी से स्नान पर अड़े शंकराचार्य अविमुक्तानंद सरस्वती और योगी सरकार के बीच चल रहे विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री ने सलाह दी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष हमारे अपने हैं, दोनों सनातनी हैं। बीच का रास्ता निकालें और मिल-बैठकर सुलह करें। सनातन का दुनिया के सामने मजाक न बनने दें। आजकल की पीढ़ी पर चुटकी लेते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने युवाओं को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया की रील्स में कीमती समय बर्बाद नहीं करें। रील से निकलकर रियलिटी से जुड़ें। अपने परिवार और समाज को समर्थ दें। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से गौ माता को राहत माता घोषित करने की मांग की। इस कथा ने इतिहास रच दिया जब मंच पर वाल्मीकि समाज और 30 गरीब परिवारों ने बाबा धीरेंद्र शास्त्री की आरती उतारी। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि रामकथा पर सबका समान अधिकार है। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद थे।



धर्म और राजनीति के बढ़ते घालमेल समाज के लिए घातक: सुश्री मायावती

लखनऊ (एजेंसी)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने धर्म और राजनीति के बढ़ते घालमेल पर गंभीर चिंता जताकर समाज के लिए घातक बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी बीते कुछ वर्षों से धार्मिक पर्वों, त्यौहारों, पूजापाठ, स्नान और अन्य आस्थागत आयोजनों में राजनीतिक हस्तक्षेप लगातार बढ़ा है। इसके कारण नए-नए विवाद, तनाव और सामाजिक संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं।

मायावती ने अपने बयान में कहा कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति से और राजनीति को धर्म से जोड़ने के गंभीर खतरे हमेशा बने रहते हैं। प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा विवाद इसका ताजा उदाहरण है, जहां आस्था के विषय को राजनीतिक रंग देने से आपसी अनादर, आरोप-प्रत्यारोप और टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज



में सौहार्द बिगाड़ती हैं और आम लोगों के मन में दुश्च व चिंता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न करती हैं।

बसपा प्रमुख मायावती ने जोर देकर कहा कि देश का संविधान और कानून जनहित और जनकल्याणकारी कार्यों को ही वास्तविक

निर्वहन कर सकते हैं। वर्तमान हालात में भी जनता की यही अपेक्षा है कि सभी वर्गों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा निष्पक्षता से की जाए।

उन्होंने प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहे विवाद को आपसी सहमति से शीघ्र सुलझाने की अपील कर कहा कि जितनी जल्दी इसका समाधान होगा, उतना ही बेहतर होगा। उल्लेखनीय है कि माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पालकी में स्नान के लिए जाते समय पुलिस द्वारा रोके जाने से विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसके बाद धक्का-मुक्की और धरना जैसी स्थिति बनी। इस प्रकारन में प्रशासन द्वारा जारी नोटिसों के बाद मामला और तूल फुटा गया तथा राजनीतिक दलों की भी इसमें एंटी हो गई। अपने बयान के अंत में मायावती ने 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर प्रशंसावर्षियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दीं।

रॉबर्ट वाड्रा मामले पर सुनवाई टली, ईडी ने मांगा अतिरिक्त समय तो कोर्ट हुआ नाराज 26 फरवरी को होगी सुनवाई

पटना (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायित्व की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर शनिवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टाल दी गई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान ईडी ने चार्जशीट से संबंधित कुछ आवश्यक दस्तावेज दायित्व



करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने नाराजी जताई। अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि जरूरी कामजात जमा करने के लिए यह एजेंसी को दिया जा रहा अंतिम अवसर है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को समय पर सभी औपचारिकाएं पूरी करनी चाहिए, ताकि न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। यह चार्जशीट ब्रिटेनस्थित डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायित्व की गई है। मामले में विदेशी संपत्तियों और कथित अवैध वित्तीय लेन-देन से जुड़े पुराने आरोपों की एक बार फिर गहन जांच की जा रही है। ईडी के

अनुसार, रॉबर्ट वाड्रा का नाम संजय भंडारी से संबंधित विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन के संदर्भ में सामने आया है। एजेंसी का आरोप है कि इन लेन-देन में मनी लॉन्ड्रिंग के तत्व मौजूद हैं, जिनकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है।

गौरतलब है कि ईडी की यह जांच वर्ष 2016 में संजय भंडारी के ठिकानों पर हुई आयकर विभागी की छापेमारी के बाद शुरू हुई थी। इस दौरान कथित तौर पर कुछ इमेल और दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिनके आधार पर जांच एजेंसियों ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगियों के साथ भंडारी के संबंधों

हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से और 5 करोड़ रुपये ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग के जरिए भेजे गए थे। जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी ने 38.69 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है, जिन्हें अपराध की कमाई या उसके समकक्ष बताया गया है।

ईडी ने जुलाई 2025 में पीएमएलए की धारा 50 के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी दर्ज किया था। वहीं, संजय भंडारी पहले से ही विदेश में अचोपित संपत्तियां रखते और अवैध वित्तीय लेन-देन के आरोपों का सामना कर रहा है। अब मामले में 26 फरवरी को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

6 महीने पहले गुजरी मां की याद में बनाई फिल्म

गोरखपुर में बनी 'हैप्पी बर्थडे' फिल्म को 'सेकेंड बेस्ट फिल्म' अवॉर्ड

संवाददाता
गोरखपुर । के रजत सिंह राजपूत की लिखी गई फिल्म 'हैप्पी बर्थडे' को गोरखपुर सिनेमा महोत्सव में सेकेंड बेस्ट फिल्म अवॉर्ड मिला। अपनी इस सफलता का श्रेय पूरी टीम को देते हुए उन्होंने बताया कि यह कहानी कहीं न कहीं मेरी ही है। मैंने देखा है कि मेरे सपने को पूरा करने के लिए माता- पिता ने कितना संघर्ष किया है। उन्होंने बताया कि मुझे फिल्म स्कूल भेजने में मेरी मां का सबसे बड़ा हाथ है। 6 महीने पहले उनका निधन हो गया। उन्हीं के याद में मैंने यह स्टोरी लिखी। मेरी यह फिल्म मेरी मां समर्पित है। 'सिनेमा वाला' फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े रजत इस समय के 'सिनेमा वाला' फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हैं। इसी प्रोडक्शन की ओर से बनाई गई फिल्म 'हैप्पी बर्थडे' को गोरखपुर



सिनेमा महोत्सव में दूसरा बेस्ट फिल्म अवॉर्ड मिला। इस फिल्म का लेखन और निर्देशन रजत सिंह राजपूत ने किया। मेन कैरेक्टर्स ने फिल्म में डाली जान फिल्म के मेन कैरेक्टर्स रजत सिंह राजपूत, अंकिता सिंह, चंदन यादव, बिक्की प्रजापति, अंतिमा यादव, तान्या जायसवाल, समरेश मिश्रा और पलक मिश्रा ने अपने इंप्रेसिव

एक्टिव से फिल्म में जान डाल दी। फिल्म का साउंड डिजाइन शिवम वर्मा ने किया, जबकि इसकी सिनेमैटोग्राफी राहुल शर्मा, अखिल, शिव नारायण सिंह चौहान और चंदन यादव ने की है। फिल्म के संपादन भी चंदन यादव ने मुख्य भूमिका निभाई है। जानिए 'हैप्पी बर्थडे' की कहानी दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए रजत ने



बताया कि फिल्म खाने की बबारी को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए रजत ने बताया कि फिल्म खाने की बबारी को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करती है दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए रजत ने बताया कि फिल्म 'हैप्पी बर्थडे' खाने की बबारी के भयावह रूप को संवेदनशील ढंग

से प्रस्तुत करती है। कहानी एक ऐसे पिता के इर्द-गिर्द घूमती है। जिसकी बेटी अपने जन्मदिन पर केक की इच्छा जताती है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पिता उसकी यह छोटी-सी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। अंत में उसे एक डैबिन में केक मिलता है उसे अपनी बेटी के लिए लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर फिल्म में एक



ऐसे परिवार को दिखाया गया है, जिसके लिए वही केक कोई महत्व नहीं रखता और उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। फिल्म का अंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। रजत ने बताया कि उनकी पूरी जो टीम है उन्हें अपने-अपने कामों में बचपन से ही रुचि रही है। सबके अलग- अलग गुण मिलकर एक मजबूत टीम बनी।

इस फिल्म की सफलता का श्रेय सभी टीम मेंबर को जाता है। हम सब की रूचि ने 'सिनेमावाला फिल्म प्रोडक्शन' को जन्म दिया है। रजत बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए कहीं और नहीं बल्कि गोरखपुर के अलग- अलग लोकेशन का इस्तेमाल किया है। हमें लोकेशन को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा आसानी से

हमने शूटिंग सॉफ्ट तय किए। फिल्म के लिए टीम को मिली ट्रॉफी रजत ने बताया कि चुंकि यह एक शार्ट स्टोरी है इसलिए इसे बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आया है। हमने इसे बहुत ही सस्ते में 80,000 की लागत में तैयार किया है। लगभग एक साल की मेहनत रंग लाई रजत ने बताया- इस फिल्म को बनाने में लगभग एक साल का समय लगा। 6 महीने पहले स्क्रिप्ट लिखी और 6 महीने में शूटिंग और बाकी काम किया है। उम्मीद है लोगों को यह काफी पसंद आए। रजत ने बताया पिछले साल गोरखपुर सिनेमा महोत्सव में हमारी फिल्म 'ड्रीम्स लगी थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म को 12 इंटरनेशनल अवॉर्ड मिल चुके हैं और यहां सेकेंड बेस्ट फिल्म अवॉर्ड मिला था।

पानी के 11 प्लांटों के लाइसेंस निलंबित, उत्पादन और बिक्री पर लगाई रोक

संवाददाता
गोरखपुर । आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के निर्देश पर चलाए गए विशेष राज्यस्तरीय जांच अभियान के तहत अंतरजनपदीय टीम ने नौ और 10 जनवरी को विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण किया था। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है, जबकि विस्तृत रिपोर्ट में पानी की रिपोर्ट असुरक्षित मिलने के आसार हैं। गोरखपुर शहर और देहात क्षेत्र में बोलबाल पानी के 11 प्लांटों में उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इंदौर में दूधित पानी पीने से बच्चों की मौत के बाद अंतरजनपदीय टीम ने नौ और 10 जनवरी को 19 प्लांटों की जांच की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खामियां मिलने पर इनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के निर्देश पर चलाए गए विशेष राज्यस्तरीय जांच अभियान के तहत अंतरजनपदीय टीम ने नौ और 10 जनवरी को विभिन्न प्लांटों का निरीक्षण किया था। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार, लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की गई है,



जबकि विस्तृत रिपोर्ट में पानी की रिपोर्ट असुरक्षित मिलने के आसार हैं। इन प्लांटों में पानी के नमूने लेने के साथ चेक लिस्ट के अनुसार भी जांच की गई थी, जिसमें खामियां मिली हैं। इन फर्मों को नोटिस दिया जा रहा है। पानी के रासायनिक और माइक्रो बायोलॉजिकल परीक्षण की अनुपलब्धता, ओजोनेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) मशीनों का खराब होना, पेस्ट कंट्रोल की व्यवस्था न होना और स्वच्छता का अभाव सहित अन्य खामियां पाई गई हैं, जबकि कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र भी सही नहीं पाए गए थे। इन फर्मों के उत्पादन व बिक्री पर रोक झा फ्लोर मिल्स प्रा. लि, ब्रांड : लाइफ इंडिया, गोडा द फार्मा

फूड्स एंड बेवरेज, ब्रांड : एनवैर, सानबरसा शॉप बेवरेज, ब्रांड : शार्प, मोहरीपुर अजय नीर उद्योग, ब्रांड : एक्वा नीर, नौसड़ एशियन एजेंसीज, ब्रांड : न्यू गैलेक्सी, गोडा एमडीएस इंटरप्राइजेज, ब्रांड : ब्लू नोवा, गोला जीके फूड्स एंड बेवरेजेज, ब्रांड : गैलीसिया, सहजनवा देवकृपा फूड एंड बेवरेजेज, प्रा. लि., ब्रांड : हाइमैक्स, नकहा सेफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ब्रांड : एक्वा रैली, राप्तीनगर रिलायबल फ्रेश, गोला शाह फूड एंड बेवरेज, गोडा आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर पानी के प्लांटों में की गई जांच में गंभीर खामियां मिलने पर 11 प्लांटों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।

मायावती बोलीं- धार्मिक मामलों में राजनीतिक दखल से बढ़ रहे विवाद...तनाव व संघर्ष का कारण बन रहे

संवाददाता
लखनऊ । बसपा सुप्रीमो मायावती ने धार्मिक आयोजनों में बढ़ते राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इससे विवाद, तनाव और संघर्ष बढ़ रहे हैं। प्रयागराज स्नान विवाद इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने संविधान की भावना के अनुरूप धर्म और राजनीति को अलग रखने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व, त्योहार, पूजापाठ, स्नान आदि में



राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप एवं प्रभाव पिछले कुछ वर्षों से बढ़ा

है। यह नए विवाद, तनाव व संघर्ष का कारण बन रहा है, जो

सही नहीं है। इससे लोगों का दुखी और चिंतित होना स्वाभाविक है। बसपा सुप्रीमो ने शनिवार को जारी अपने बयान में कहा कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति तथा राजनीति को धर्म से जोड़ने के खतरे हमेशा बने रहते हैं। प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा विवाद, एक-दूसरे का अनादर व आरोप-प्रत्यारोप इसका ताजा उदाहरण है। इससे हर हाल में बचना ही बेहतर होगा। देश का संविधान व कानून ईमानदारी से जनहित व जनकल्याणकारी कर्म को ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानकर राजनीति को धर्म से तथा धर्म को

राजनीति से दूर रखता है। जिस पर सही नीयत व नीति से अमल हो ताकि राजनेता अपना संवैधानिक दायित्व बिना किसी द्वेष व पक्षपात के सर्वसमाज के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक हित में ईमानदारी व निष्ठापूर्वक निभा सकें। वर्तमान हालात में भी लोगों की यही अपेक्षा है। लिहाजा प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझ जाए, उतना बेहतर होगा। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने प्रदेशवासियों को हड़तर प्रदेश दिवसहू की बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं।

पांच बार से अधिक चालान पर 10,050 वाहनों का पंजीकरण निलंबित, छह महीने में नहीं भरे चालान तो ऐसा होगा

संवाददाता
लखनऊ । लखनऊ में यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले 10,050 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। छह माह में चालान न भरने पर पंजीकरण निरस्त होगा। कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट पर आरटीओ प्रशासन ने की है। यातायात नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वाले 10,050 वाहनों का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। यदि छह महीने के भीतर चालान नहीं भरे गए तो इन वाहनों का पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। यह कार्रवाई ट्रांसपोर्टनर आरटीओ की ओर से चार महीनों में की गई है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से ट्रैफिक पुलिस ने वर्ष 2025 के नवंबर तक पांच या उससे अधिक बार नियमों का उल्लंघन करने वाले



वाहनों की पहचान की। आरटीओ प्रशासन को 52,187 वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की रिपोर्ट भेजी गई थी। जांच में 5012 वाहन डुल्कीट डेटा वाले और 5298 वाहन अन्य जिलों व प्रांतों के पाए गए। ऐसे वाहनों के पंजीकरण के लिए संबंधित जिलों को ई-मेल द्वारा संसूति की गई है। एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर में ट्रैफिक पुलिस

द्वारा सीपी गई सूची के आधार पर 10050 वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया जा चुका है, जबकि शेष वाहनों के निलंबन की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, लगभग 500 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं। पंजीकरण और डीएल निलंबित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को पहली सूची में 13,919 वाहनों का विवरण सौंपा था।

कंबल वितरण समारोह में विवाद, पूर्व प्रमुख पति की तहरीर पर सभासद पर मामला दर्ज



संवाददाता
गोरखपुर । विवाद के दौरान थानेदार मौके पर पहुंचे और मंच पर हो रहे झगड़े को रोकते हुए संदीप गुप्ता को थाने भेज दिया। थोड़ी देर बाद मामला शांत होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर नाराज क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह और आनंद शाही के समर्थकों ने सड़क पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कंबल वितरण समारोह में सभासद व पूर्व प्रमुख के बीच विवाद के बाद थानाप्रभारी से बातचीत करने विध नगर पंचायत पिपाइच की ओर से आयोजित कंबल वितरण समारोह के दौरान शुक्रवार दोपहर रामलीला मैदान में पूर्व प्रमुख आनंद शाही और सभासद संदीप गुप्ता के बीच विवाद हो गया। इस

घटना के बाद पूर्व प्रमुख पति प्रेम पासवान की तहरीर पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान थानेदार मौके पर पहुंचे और मंच पर हो रहे झगड़े को रोकते हुए संदीप गुप्ता को थाने भेज दिया। थोड़ी देर बाद मामला शांत होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर नाराज क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह और आनंद शाही के समर्थकों ने सड़क पर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। थानाध्यक्ष अनुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाया और तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



विवाद का इंजन है, और विकसित भारत का भी इंजन बनेगा। यह श्रीराम, कृष्ण, शिव, बुद्ध की धरती है। प्रेरणा स्थल पर पहली बार आया हूं। यहां तीन महान विभूतियों की मूर्ति लगी है। यह स्थल राष्ट्र की जागृत का स्थल बनेगा। यह दर्शकों तक देश को दिशा देगा। 65 एकड़ में पहले कूड़े का पहाड़ था। भाजपा



सरकार ने कूड़े को कंचन में बदला है। यूपी के विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन पूरी दुनिया को मिलेंगे शाह ने सीएम युवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों को सम्मानित किया। कहा कि सीएम युवा योजना से युवाओं को ऋण देने की व्यवस्था है। अब तक 1.30 लाख युवाओं को करोड़ों का ऋण दिया गया।

विधानसभा चुनाव की बात करते हुए कहा कि मैं 2017 को याद करूंगा। यूपी का घोषणा पत्र बना रहा था। इसमें ओडीओपी को शामिल किया। डबल इंजन सरकार का काम यूपी ही नहीं पूरे देश में फैल गया है। रोजगार का साधन बना है। आज यहां ओडीओपी का मेला लगा है। विश्व प्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजन पूरी दुनिया को मिलेंगे शाह ने सीएम युवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच जिलों को सम्मानित किया। कहा कि सीएम युवा योजना से युवाओं को ऋण देने की व्यवस्था है। अब तक 1.30 लाख युवाओं को करोड़ों का ऋण दिया गया।

होगी। अलग-अलग चरण में इसका काम होगा। यूपी का हर जिला रोजगारयुक्त होगा। देशभर में जाने वाले को यूपी में रोजगार की व्यवस्था होगी। अपने माता-पिता की सेवा करें। 15 लाख करोड़ की योजना जमीन पर उतरी शाह ने आगे कहा पीएम के नेतृत्व में सीएम योगी ने योजनाओं को जमीन पर उतारा। कग्रिस, सपा, बसपा ने बीमारू राज्य को ब्रेक थू राज्य बनाया है। कृषि विकास दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। यूपी फूड बास्केट बना है। अयोग्या में श्रीराम का मंदिर बनाने का काम हुआ। महाकुंभ का आयोजन, सनातन धर्म की ख्याति को पहुंचाया। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात कर रहा है। कोई 2017 के पहले कल्पना नहीं कर सकता था। आज ग्रीन डेस्टिनेशन बन गया है। 15 लाख

करोड़ की योजना जमीन पर उतारने का काम किया है। डकैती, लूट में कमी आई। देश की सीमा को भी सुरक्षित किया है। यूपी विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ा है। देशभक्ति की लौ जागृत हो चुकी है। परिवारवादी पार्टियां यूपी का कल्याण नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगला साल चुनाव का साल है। यूपी के विकास के लिए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएं। परिवारवादी पार्टियां यूपी का कल्याण नहीं कर सकती हैं। भाजपा ही कर सकती है। मोदी, योगी ने विकास का सर्वश्रेष्ठ दिया है। डिफेंस कारिडोर, एक्सप्रेसवे, हाईवे दिए। ग्रंथचार समाप्त किया। गरीब के लिए योजनाएं आईं। 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। आने वाले चुनाव में हर मतदाता जाति-पंथ से ऊपर उठकर भाजपा का कमल खिलाए।